एच-1बी पर 98 लाख लगेगी फीस

नए बीजा प्रस्ताव के बाद अमेरिका में भारतीयों को नौकरी नहीं होगी आसान

वॉशिंगटन, 24 अगस्त, एजेंसी. अमेरिका में नौकरी करने का सपना देख रहे विदेशी हाई-स्किल प्रोफेशनल्स के लिए एच-1बी बीजा से जुड़ा नया प्रस्ताव चर्चा में है. डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासन ने वीजा पर 1,03,265 डॉलर यानी करीब 98 लाख रुपए की अतिरिक्त फीस लगाने का प्रस्ताव जारी किया है.

एच-1बी बीजा अमेरिकी कंपनियों को विदेशों से विशेष कौशल वाले कर्मचारियों को अस्थायी तौर पर नियुक्त करने की अनुमति देता है. प्रस्ताव लागू होने पर मौजूदा आवेदन लागत की तुलना में कंपनियों पर बड़ा अतिरिक्त वित्तीय भार पड़ सकता है. मौजूदा व्यवस्था में एच-1बी आवेदन के लिए कंपनियों को लगभग 2,000 से 5,000 डॉलर तक शुल्क देना पड़ता है. प्रस्तावित रकम इससे कई गुना अधिक है. नया नियम इस साल के अंत तक लागू हो सकता है. इस प्रस्ताव का भारतीय युवाओं पर सबसे ज्यादा असर पड़ने वाला है. एच-1बी कार्यक्रम का इस्तेमाल भारतीय आईटी और टेक्नोलॉजी प्रोफेशनल्स बड़े पैमाने पर करते हैं. हालांकि, प्रस्ताव लागू होने और इसकी अंतिम शर्तों को लेकर आगे की प्रक्रिया महत्वपूर्ण होगी.

यूएस में भारतीय मूल की आबादी

वर्ष	भारतीय
2026 करीब	55 लाख
2025	54 लाख
2024	52 लाख

पहले भी विवादों में रही है भारी फीस

पिछले साल ट्रम्प प्रशासन ने एक अस्थायी आदेश के जरिए ऐसी फीस लागू की थी. जून में अमेरिकी फेडरल कोर्ट ने इसे गैरकानूनी करार देते हुए सरकार को शुल्क वसूलने से रोक दिया था. मामला अभी पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है. बोस्टन की अपीलीय अदालत फैसले की समीक्षा कर रही है, जबकि वॉशिंगटन डीसी की एक अन्य अदालत में कारोबारी संगठन की याचिका पर सुनवाई से जुड़ी प्रक्रिया जारी है.

बंगाल में बड़े झटके के बाद ममता ने स्पष्ट कर दिया भविष्य का राजनीतिक प्लान

संन्यास नहीं लूंगी, भाजपा से लड़ूंगी

नवभारत न्यूज नेटवर्क

कोलकाता, 25 अगस्त. पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अपने राजनीतिक भविष्य को लेकर स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा कि वह राजनीति से संन्यास लेने वाली नहीं हैं. उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को राजनीतिक रूप से पीछे धकेलने तक उनका संघर्ष जारी रहेगा.

ममता बनर्जी ने यह टिप्पणी सोशल मीडिया मंच फेसबुक पर लाइव संबोधन के दौरान की. उनका बयान ऐसे समय आया है, जब तृणमूल कांग्रेस के भीतर बगावत और संगठनात्मक खींचतान की खबरें सामने आ रही हैं. ममता ने कहा कि केवल बैठक की अनुमति नहीं मिलने के कारण उनके राजनीति से हटने की उम्मीद करने वाले लोग गलतफहमी में हैं.

उन्होंने दावा किया कि राज्य की सत्ता में बदलाव के कुछ महीनों के भीतर ही लोगों ने भाजपा का कथित तौर पर असली चेहरा देख लिया है.

बदले की भावना से दर्ज हो रहे केस

पूर्व मुख्यमंत्री ने लोकतांत्रिक आंदोलनों की आवाज दबाने का भी आरोप लगाया. उन्होंने पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया कि तृणमूल कांग्रेस कार्यकर्ताओं के खिलाफ मामले दर्ज किए जा रहे हैं. ममता के मुताबिक बड़ी संख्या में लोगों के खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए हैं और कुछ लोगों की मदद से कार्यकर्ताओं को भाजपा में शामिल होने के लिए कहा जा रहा है.

उन्होंने पुलिस अधिकारियों की भूमिका पर भी आपत्ति जताई और आरोप लगाया कि कुछ अधिकारी राजनीतिक पदाधिकारियों की तरह व्यवहार कर रहे हैं. पूर्व मुख्यमंत्री ने यादवपुर विश्वविद्यालय में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और वामपंथी छात्रों के बीच हुई झड़पों का भी जिक्र किया. उन्होंने भाजपा पर परिसर में अशांति और तोड़फोड़ करवाने का आरोप लगाया. हालांकि उन्होंने कहा कि राजनीतिक मतभेदों के बावजूद छात्रों के प्रति सम्मान बना रहना चाहिए.

हिम्मत है तो गुजरात के स्कूल दिखाओ

नवभारत न्यूज नेटवर्क

नई दिल्ली, 25 अगस्त. आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने पंजाब के सरकारी स्कूलों को लेकर भारतीय जनता पार्टी की ओर से किए जा रहे दावों पर पलटवार किया है. उन्होंने भाजपा को गुजरात और पंजाब के एक-एक हजार सरकारी स्कूलों का संयुक्त निरीक्षण कराने की चुनौती दी.

- आप प्रमुख केजरीवाल ने बीजेपी को दी खुली चुनौती
- भाजपा पंजाब की पुरानी तस्वीरों से कर रही बदनाम
- पंजाब में 19000 सरकारी स्कूलों की हालत बेहतर

केजरीवाल ने कहा कि भाजपा गुजरात के 1000 स्कूलों की सूची दे और आम आदमी पार्टी पंजाब के 1000 विद्यालयों की सूची उपलब्ध कराए. इसके बाद दोनों राज्यों के संस्थानों की स्थिति का मिलकर जायजा लिया जाए. वीडियो संदेश में केजरीवाल ने आरोप लगाया कि भाजपा पंजाब के सरकारी स्कूलों को बदनाम करने के लिए पुराने वीडियो का इस्तेमाल कर रही है. उन्होंने दावा किया कि जिस विद्यालय का वीडियो भाजपा की ओर से साझा किया जा रहा है, वह वर्ष 2018 का है. उनके मुताबिक उस समय पंजाब में कांग्रेस की सरकार थी. केजरीवाल ने कहा कि गलतियों की ओर ध्यान दिलाया जाए तो उन्हें सुधारने के लिए सरकार तैयार है, लेकिन गलत या पुराने वीडियो के जरिये राज्य की छवि खराब नहीं की जानी चाहिए. आप नेता ने कहा कि गुजरात में लंबे समय से भाजपा की सरकार है, जबकि पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार को करीब साढ़े चार वर्ष हुए हैं. इसी आधार पर उन्होंने दोनों राज्यों के विद्यालयों की स्थिति की प्रत्यक्ष तुलना करने का प्रस्ताव रखा.

स्कूल में हिजाब पहनने की अनुमति नहीं मिलेगी : कोर्ट

छात्रा की याचिका खारिज

प्रयागराज, 25 नवभारत न्यूज अगस्त. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रयागराज के एक निजी स्कूल में तय ड्रेस के साथ स्कार्फ अथवा हिजाब पहनने की अनुमति मांगने वाली छात्रा की याचिका खारिज कर दी है.

न्यायमूर्ति जेजे मुनीर और न्यायमूर्ति इंद्रजीत शुक्ला की खंडपीठ ने कहा कि विद्यालय की निर्धारित वर्दी विद्यार्थियों में समानता, अनुशासन और संस्थागत पहचान को मजबूत करती है. अदालत ने माना कि एक समान ड्रेस व्यवस्था सभी समुदायों के विद्यार्थियों पर समान रूप से लागू होती है और इससे धर्मनिरपेक्ष शैक्षणिक वातावरण बनाए रखने में मदद मिलती है. मामला प्रयागराज के अत्तरसुइया स्थित टैगोर पब्लिक स्कूल की छात्रा सुकैना रिजवी से जुड़ा है. छात्रा ने हाईस्कूल की पढ़ाई इसी संस्थान से पूरी की थी और कक्षा 11 में प्रवेश लेना चाहती थी. उसका कहना था कि वह कक्षा छह से स्कार्फ पहनकर विद्यालय आती रही है और उस दौरान स्कूल प्रबंधन ने कोई आपत्ति नहीं जताई.

वांगचुक फिर आंदोलन की राह पर

लद्दाख हिंसा की बरसी पर एक माह तक स्वतंत्र राज्य के लिए प्रदर्शन का ऐलान

नवभारत न्यूज नेटवर्क

नई दिल्ली, 25 अगस्त. लद्दाख में 24 सितंबर 2025 को हुई हिंसा की बरसी से पहले आंदोलन का मुद्दा फिर गरमा गया है. लेह में आयोजित कैंडल मार्च में सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने पिछले साल जान गंवाने वाले लोगों को याद किया और कहा कि अगले एक माह तक उन्हें श्रद्धांजलि देने के साथ न्याय और जवाबदेही की मांग उठाई जाएगी.

उन्होंने स्पष्ट किया कि शुरुआती कार्यक्रम प्रतीकात्मक है, जबकि आगे व्यापक और शांतिपूर्ण प्रदर्शन किए जाएंगे.

वांगचुक के मुताबिक, लद्दाख के लोग पिछले कई वर्षों से राज्य का दर्जा, संविधान की छठी अनुसूची में शामिल किए जाने, रोजगार की सुरक्षा और स्थानीय अधिकारों से जुड़े मुद्दों को लेकर केंद्र के सामने अपनी मांग रखते रहे हैं. उनका कहना है कि बातचीत में अपेक्षित प्रगति नहीं होने के कारण लोगों में असंतोष बढ़ा है.

जांच पर भी उठाए सवाल

उन्होंने 24 सितंबर 2025 की घटना की न्यायिक जांच को लेकर भी सवाल उठाया. केंद्र सरकार ने पूर्व सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीश जस्टिस बीएस चौहान की अध्यक्षता में जांच आयोग गठित किया था. आयोग को हिंसा की परिस्थितियों, सुरक्षा बलों की कार्रवाई और हुई मौतों की जांच करनी है. लद्दाख प्रशासन के अनुसार आयोग ने प्रशासनिक अधिकारियों के बयान दर्ज किए हैं और सार्वजनिक हलफनामे भी प्राप्त किए हैं. हालांकि, अभी तक रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं हुई है. मई 2026 में केंद्र और लद्दाख के प्रतिनिधियों के बीच कई मुद्दों पर बातचीत हुई थी.

एक नजर में

योगी 1 लाख युवाओं को देंगे नौकरी

लखनऊ, 25 अगस्त (नवभारत न्यूज). उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले युवाओं को सरकारी रोजगार देने को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को बड़ा ऐलान किया. उन्होंने कहा कि अगले छह महीनों में प्रदेश के एक लाख युवाओं को सरकारी नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे. इसके लिए अलग-अलग चरणों में हर सप्ताह कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे. मुख्यमंत्री के मुताबिक संबंधित भर्ती परीक्षाएं पूरी हो चुकी हैं और अब परिणाम जारी करने की प्रक्रिया चल रही है. उन्होंने आयोगों और भर्ती बोर्डों से परिणाम की समयसीमा और कम करने को कहा है.

ईरान ने फिर पेश की मोजतबा की मौजूदगी

तेहरान, 25 अगस्त. ईरान में सुप्रीम लीडर मोजतबा खामेनेई की सेहत और सार्वजनिक गतिविधियों को लेकर चल रही अटकलों के बीच एक नया वीडियो सामने आया है. ईरानी मीडिया के मुताबिक, फुटेज में मोजतबा एक धार्मिक अकादमिक अध्ययन सत्र की अध्यक्षता करते दिखाई दे रहे हैं. वीडियो ईरान की फार्स न्यूज एजेंसी ने सार्वजनिक किया. हालांकि, रिकॉर्डिंग कब की है, इसकी कोई स्पष्ट तारीख नहीं बताई गई है. यह दृश्य उस समय का है जब मोजतबा देश के सर्वोच्च नेता नहीं बने थे. फुटेज में वह कुछ लोगों के बीच बैठे नजर आते हैं. चर्चा शुरू होने से पहले मौजूद लोग प्रार्थना करते दिखाई देते हैं. इसके बाद मोजतबा छात्रों को इस्लामिक सिक्योरिटी मॉडल विषय पर संबोधित करते सुनाई देते हैं.

पाकिस्तान की सरहद यूनिवर्सिटी में बवाल

इस्लामाबाद, 25 अगस्त. सरहद यूनिवर्सिटी के रावत कैंपस में 24 अगस्त को छात्रों का एक समूह फीस और कक्षा समय को लेकर विभागीय प्रमुख के खिलाफ प्रदर्शन कर रहा था. उपलब्ध जानकारी के अनुसार, स्टूडेंट अफेयर्स की प्रमुख डॉ. आइना विद्यार्थियों को समझाने के लिए मौके पर पहुंचीं. कुछ छात्रों के पीछे नहीं हटने पर उन्होंने अपने पति को परिसर में बुलाया, जो पाकिस्तानी सेना में अधिकारी बताए जा रहे हैं. प्रत्यक्षदर्शी के अनुसार, सैन्य अधिकारी वर्दी में परिसर पहुंचे और प्रदर्शन कर रहे छात्रों के साथ कथित तौर पर मारपीट की. इसके बाद उन्होंने अपनी सर्विस पिस्टल निकाली और हवा में गोली चलाई.

फॉक्सवैगन में 1 लाख नौकरियों पर संकट

वोल्फ्सबर्ग, 25 अगस्त. जर्मनी की वाहन निर्माता कंपनी फॉक्सवैगन में लागत घटाने और कारोबार का आकार कम करने की प्रस्तावित योजना को लेकर कर्मचारियों के बीच असंतोष बढ़ गया है. मुख्य कार्यकारी अधिकारी ओलिवर ब्लूम वोल्फ्सबर्ग स्थित कंपनी की प्रमुख फैक्ट्री में कर्मचारियों के सामने बदलावों की रूपरेखा रखेंगे. प्रस्तावित कदमों से करीब एक लाख कर्मचारियों के रोजगार पर असर पड़ सकता है. इसके बाद जर्मनी के अन्य संयंत्रों में भी कर्मचारियों के साथ बैठकें प्रस्तावित हैं. फॉक्सवैगन इस समय कई कारोबारी चुनौतियों से गुजर रही है.

बढ़े दामों के बाद चीनी की जमाखोरी पर सरकार सख्त

- आयातित चीनी 60 दिन में बाजार में उतारनी होगी
- 31 अक्टूबर तक 10 लाख टन चीनी आयात की अनुमति

नवभारत न्यूज

नई दिल्ली, 25 अगस्त. चीनी की बढ़ती कीमतों पर नियंत्रण के लिए केंद्र सरकार ने आयातित चीनी को लेकर नियम कड़े कर दिए हैं.

टैरिफ रेट कोटा के तहत आने वाली कच्ची चीनी को अब देश में पहुंचने की तारीख से 60 दिनों के भीतर रिफाइंड कर बाजार में बेचना अनिवार्य होगा. सरकार ने 31 अक्टूबर 2026 तक 10 लाख टन चीनी आयात की अनुमति दी है. इस कदम का उद्देश्य आयातित माल को लंबे समय तक गोदामों में रखने और संभावित जमाखोरी पर रोक लगाना है. नए प्रावधानों के मुताबिक बिल ऑफ एंट्री की तारीख से दो महीने के भीतर कच्ची चीनी की प्रोसेसिंग पूरी करनी होगी और तैयार उत्पाद को घरेलू बाजार में उतारना होगा. पहले आयातित कच्ची चीनी को प्रोसेस कर 31 अक्टूबर तक बाजार में उपलब्ध कराने की शर्त थी. अब प्रत्येक खेप के लिए 60 दिन की समयसीमा तय की गई है. सरकार ने केवल आयात की समयसीमा ही नहीं बदली है, बल्कि घरेलू बाजार में उपलब्ध स्टॉक की निगरानी भी बढ़ाई है.

असम में 9000 करोड़ का सुपर हाईवे

नवभारत न्यूज नेटवर्क

गुवाहाटी, 25 अगस्त. असम में प्रस्तावित गुवाहाटी-तेजपुर कॉरिडोर को पूर्वोत्तर की परिवहन व्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण परियोजना माना जा रहा है. 135.87 किलोमीटर लंबा यह मार्ग बैहाटा चारियाली से शुरू होकर तेजपुर तक जाएगा.

परियोजना को बिल्ड-ऑपरेट-ट्रांसफर मॉडल पर विकसित किया जाएगा. इसके निर्माण पर करीब 9,000 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है. नए मार्ग से गुवाहाटी और तेजपुर के बीच आवागमन अधिक तेज होने की उम्मीद है. परियोजना पूरी होने पर यात्रा समय में करीब आधी तक कमी आ सकती है. कॉरिडोर में कुल 58.7 किलोमीटर लंबे पांच बाईपास प्रस्तावित हैं. ये बैहाटा चारियाली, सिपाझार, खारूपेटिया, डेकियाजुली और तेजपुर में बनाए जाएंगे. इनका उद्देश्य आबादी वाले क्षेत्रों से गुजरने वाले यातायात को अलग मार्ग देना और स्थानीय सड़कों पर दबाव कम करना है. प्रस्तावित ढांचे में एक हाथी अंडरपास, 15 बड़े पुल, 30 छोटे पुल, 19 फ्लाईओवर और करीब 210 किलोमीटर सर्विस रोड शामिल हैं. हाथी अंडरपास का उद्देश्य वन्यजीवों की आवाजाही के लिए सुरक्षित रास्ता उपलब्ध कराना है.

135 किमी का नया हाईवे बदलेगा कनेक्टिविटी का नक्शा

आज का इतिहास

1609: वैज्ञानिक और खगोलशास्त्री गैलीलियो गैलीली ने वेनिस के शासकों के सामने पहली शक्तिशाली दूरबीन का प्रदर्शन किया था.

1825: उरुग्वे ने ब्राजील के साम्राज्य से अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की थी.

1944: द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान चार साल के नाजी कब्जे के बाद पेरिस शहर को आजाद कराया गया.

1957: भारतीय पोलो टीम ने विश्व कप जीता था.

अमेजन, स्विगी के लाइसेंस सस्पेंड

बेंगलुरु. कर्नाटक खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन ने ऑनलाइन मंचों पर जहरीले धतूरे के फल और बीजों की खाद्य पदार्थ के रूप में बिक्री पाए जाने के बाद बड़ी कार्रवाई की है. विभाग ने अमेजन, स्विगी, इंस्टामार्ट और बिगबास्केटके खाद्य लाइसेंस अगले आदेश तक निलंबित करने का आदेश दिया है. साथ ही तीनों मंचों को इंसानों के सेवन के लिए धतूरे से जुड़ी सभी सूची, विज्ञापन और प्रचार सामग्री तत्काल हटाने तथा इसकी खाद्य वस्तु के रूप में बिक्री और वितरण रोकने के निर्देश दिए गए हैं. मामले की शुरुआत स्विगी इंस्टामार्ट के जरिये भेजे गए धतूरे के फलों के एक पैकेट को लेकर ग्राहक की शिकायत से हुई.

राहुल ने जनगणना पर साधा निशाना

नवभारत न्यूज

नई दिल्ली, 25 अगस्त. कांग्रेस नेता राहुल गांधी और पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर जनगणना-2027 में जातिगत आंकड़े जुटाने की प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैं.

दोनों नेताओं ने कहा है कि जातियों के नाम दर्ज करने के लिए केवल खुला विकल्प रखने से एक ही समुदाय अलग-अलग नामों या उपजातियों के रूप में दर्ज हो सकता है. इससे वास्तविक संख्या का आकलन और विभिन्न क्षेत्रों के आंकड़ों की तुलना कठिन होने की आशंका है. पत्र में कांग्रेस नेताओं ने प्रश्नावली को अंतिम रूप देने से पहले राजनीतिक दलों, विशेषज्ञों और आम लोगों से सलाह लेने की मांग की है. उन्होंने विशेष रूप से जनगणना के सवालों में 'पिछड़ा वर्ग' शब्द का स्पष्ट उल्लेख नहीं होने पर आपत्ति जताई. उनका कहना है कि इससे ओबीसी आबादी से जुड़े आंकड़ों को व्यवस्थित तरीके से जुटाने में समस्या पैदा हो सकती है. राहुल गांधी और खड़गे ने जातियों की पहचान के लिए एक समान व्यवस्था अपनाने का सुझाव दिया है. इसके लिए सरकारी जाति सूचियों और भारतीय मानवशास्त्रीय सर्वेक्षण से संबंधित सूची का उपयोग करने तथा तय विकल्प या ड्रॉप-डाउन व्यवस्था देने की मांग की गई है. उन्होंने बिहार और तेलंगाना में अपनाई गई प्रक्रियाओं का उदाहरण भी दिया है. केंद्र की ओर से 14 अगस्त को जनगणना-2027 में पूछे जाने वाले 40 सवालों की सूची जारी की गई थी.

जाति में विकल्प से फैलेगा भ्रम

इसमें पहली बार आजादी के बाद सभी समुदायों की जातिगत जानकारी दर्ज करने का प्रावधान बताया गया है. जाति संबंधी प्रश्न सूची में 10वें स्थान पर है और इसमें एससी, एसटी के साथ जाति का विकल्प भी शामिल किया गया है. आगामी जनगणना देश की पहली डिजिटल जनगणना होगी. इसमें डेटा इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से दर्ज करने के साथ लोगों को स्वयं जानकारी उपलब्ध कराने यानी सेल्फ-एन्यूमरेशन की सुविधा भी दी जाएगी. केंद्र ने व्यक्तिगत विवरण को गोपनीय रखने का प्रावधान बताया है. सरकार ने इस पूरी प्रक्रिया के लिए 11,718.24 करोड़ रुपये के बजट को मंजूरी दी है.

पंजाब में अकेले उतरेगी बसपा

मायावती ने गठबंधन पर साफ किया रुख

नवभारत न्यूज

लखनऊ/चंडीगढ़, 25 अगस्त. पंजाब की सियासत में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक दल अपनी-अपनी रणनीति को धार देने में जुट गए हैं. बहुजन समाज पार्टी ने राज्य में किसी भी दल के साथ चुनावी गठबंधन नहीं करने का फैसला किया है.

पार्टी अध्यक्ष मायावती ने लखनऊ स्थित केंद्रीय कार्यालय में पंजाब के वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक के दौरान यह घोषणा की. उन्होंने कहा कि बसपा उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की तरह पंजाब में भी अपने दम पर चुनाव लड़ेगी. पार्टी के अनुसार, पहले किए गए गठबंधनों से उसे अपेक्षित राजनीतिक लाभ नहीं मिला और सीटों के साथ मत प्रतिशत पर भी प्रतिकूल असर पड़ा.

मायावती ने संगठन को मजबूत करने, जनाधार बढ़ाने और कार्यकर्ताओं को चुनावी तैयारियों में सक्रिय करने पर जोर दिया. बैठक में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवार चयन और संगठनात्मक गतिविधियों की समीक्षा भी की गई. बसपा की रणनीति आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और भाजपा के सामने खुद को एक अलग राजनीतिक विकल्प के रूप में पेश करने की है. मायावती ने पार्टी नेताओं को आर्थिक सहयोग बेहतर करने तथा निर्धारित कार्यक्रमों को प्रभावी ढंग से आयोजित करने के निर्देश भी दिए.

हस्तियों के ट्वीट

प्रसिद्ध भारतीय उद्यमी, लेखक और पॉडकास्टर राज शमानी ने मानसिक आराम और काम के बीच संतुलन को लेकर सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर एक महत्वपूर्ण बात साझा की है. उन्होंने कहा कि काम से ब्रेक लेने का मतलब यह नहीं है कि व्यक्ति कंप्यूटर या काम की स्क्रीन छोड़कर फोन की स्क्रीन पर समय बिताने लगे. राज शमानी ने लिखा कि जब हम काम के दौरान फोन चलाते हैं, सोशल मीडिया देखते हैं या लगातार किसी न किसी तरह की जानकारी ग्रहण करते रहते हैं, तब हमारा दिमाग वास्तव में आराम नहीं कर रहा होता.

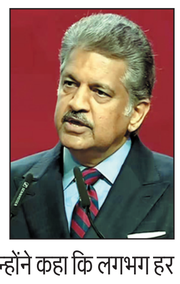

अरबपति कारोबारी और महिंद्रा समूह के चेयरमैन आनंद महिंद्रा ने अरुणाचल प्रदेश के इटानगर की टिंकल गोंगो के आत्मविश्वास और जज्बे की जमकर सराहना की है. उन्होंने सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर एक पोस्ट साझा कर टिंकल की कहानी और उनके बेबाक अंदाज को प्रेरणादायक बताया. आनंद महिंद्रा ने लिखा कि अब तक ज्यादातर लोग टिंकल गोंगो का वीडियो देख चुके होंगे और उनकी कहानी से परिचित हो गए होंगे. उन्होंने कहा कि लगभग हर मीडिया संस्थान ने उनकी कहानी को जगह दी है.

Kolhapur Municipal Corporation
Property Tax Department

कोल्हापूर महानगरपालिका

Tender Notice No. 49 - Extension due to Pre-Bid Meeting

Online bids are invited from eligible bidders for Selection of Agency for Providing Services for Assisting Numbering, Survey, and Assessment of all Properties on Revenue Generation Sharing Basis Model and Providing Required Software and Hardware for Kolhapur Municipal Corporation. The tender document containing the terms and conditions and the response of the Kolhapur Municipal Corporation regarding the objections/queries raised during the Pre-Bid Meeting has been published on the www.mahatenders.gov.in portal. The said tender process has been extended up to 04/09/2026.

Sd/-
Commissioner
Kolhapur Municipal Corporation

कार्यालय नगरपालिका परिषद, सिवनी (म.प्र.)

क्रमांक /3724/ न.पा.प./ 2026 — **ई-निविदा आमंत्रण सूचना** — सिवनी, दिनांक :- 25/08/2026

निम्नलिखित कार्यों हेतु केद्रीकृत प्रणाली में पंजीकृत फर्म/ठेकेदारों से निविदा आमंत्रित की जाती है। उल्लेखित कार्य का विस्तृत विवरण बेबसाईट https://mptenders.gov.in/ पर देखा जा सकता है ।

क्र.	टेंडर क्रमांक जारी दिनांक	प्रस्तावित निर्माण कार्य का नाम	कार्य की समयावधि एवं लागत	निविदा प्रपत्र शुल्क EMD	निविदा की अंतिम तिथि
1	2	3 4 5	6		
1.	2026_UAD_532132_1	अम्बेडकर वार्ड में गोलू डागौर के मकान से सिलपेन्द्र वानखेड़े के मकान तक आर.सी.सी. नाली निर्माण कार्य ।	45 दिवस 599720	2000 6000	11/09/2026
2.	2026_UAD_532133_1	पृथ्वीराज चौहान वार्ड में सोमवारी चौक स्थित श्री संकट मोचन व्यायामशाला के चारों ओर बाउण्ड्रीवाल एवं गेट निर्माण कार्य।	60 दिवस 976487	2000 9800	11/09/2026
3.	2026_UAD_532135_1	अम्बेडकर वार्ड में मोक्षधाम पहुंच मार्ग पर आर. सी.सी. पुलिया एवं सी.सी. रोड निर्माण कार्य।	60 दिवस 790187	2000 7950	11/09/2026
4.	2026_UAD_532138_1	रानी दुर्गावती वार्ड मे जालम सिंह मानाठाकुर के मकान से विमल अग्रवाल के मकान तक सी.सी. रोड निर्माण कार्य।	30 दिवस 435612	2000 4400	11/09/2026

नोट :- निविदा से संबंधित किसी भी प्रकार के संसोधन का प्रकाशन ऑनलाईन www.mptenders.gov.in/ वेबसाईट पर ही किया जावेगा। पृथक से समाचार पत्र में प्रकाशन नहीं किया जावेगा ।

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर पालिका परिषद सिवनी